नव भारत
राष्ट्रहित सर्वोपरि 1934 से

5 योगी ने शिक्षकों को दी बड़ी सौगात

6 ईरान को हराना इतना आसान नहीं

7 व्यापार-तकनीक सहयोग पर फोकस

10 न्यूजीलैंड टीम की दमदार जीत

एक नजर में

परीक्षा से जुड़ी जानकारी न करें शेयर : सीबीएसई

नई दिल्ली. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की कॉपियों की जांच कर रहे शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है. बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी जानकारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करना सख्त रूप से प्रतिबंधित है. सीबीएसई के अनुसार, हाल ही में सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट और कमेंट्स सामने आए हैं, जिनमें कॉपी जांच प्रक्रिया को लेकर भ्रामक या तथ्यहीन जानकारी साझा की जा रही है. इससे छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ सकता है.

एप्स्टीन से जुड़े कंटेंट सोशल मीडिया से हटाएं

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी की याचिका पर अहम आदेश दिया है. जस्टिस मिनी पुष्करणा ने सोशल मीडिया यूजर्स पर पुरी की बेटी को जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाली सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया से उस कंटेंट को 24 घंटे के अंदर हटाने का निर्देश दिया है, जो हिमायनी को अमेरिकी दोष सिद्ध यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जोड़ता है. हाईकोर्ट ने इस प्रकार की सामग्री के प्रकाशन और प्रसार पर भी रोक लगा दी है. बता दें कि हिमायनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द

नई दिल्ली. लोकसभा ने मंगलवार को ध्वनि मत से विपक्ष के आठ सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह प्रस्ताव तब पेश किया, जब कांग्रेस के मुख्य सचेतक के. सुरेश ने कुछ सदस्यों द्वारा की गई 'अनजाने में हुई चूक' के लिए खेद व्यक्त किया. समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और एनसीपी (एसपी) की सुप्रिया सुले ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. धर्मेंद्र यादव ने कहा, लोकसभा की सत्ता पक्ष की बेंचों को भी सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए. लोकसभा में कांग्रेस के सुरेश ने कहा, सदन चलाने में सहयोग के लिए तैयार हैं. विपक्ष को बोलने का समान अवसर मिलना चाहिए. वहीं, केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची जानी चाहिए.

पाक की 'नापाक' एयरस्ट्राइक

काबुल के अस्पताल पर बम गिराकर 400 लोगों की जान ली

इस्लामाबाद, 17 मार्च. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान ने राजधानी काबुल के एक अस्पताल को एयरस्ट्राइक में निशाना बनाया है. इसमें 400 लोगों की जान चली गई और 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए.

रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुलअमान, अरजान कीमत, खैरखाना और काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कई जगहों पर धमाकों और गोलीबारी की आवाजें सुनी गईं. हालांकि, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मोशर्रफ जैदी ने इन आरोपों को वेबुनियाद बताया और कहा कि काबुल में किसी अस्पताल को निशाना नहीं बनाया गया. तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शराफत जमान ने बताया कि काबुल में नशा मुक्ति केंद्र के तौर पर इस्तेमाल हो रहे एक अस्पताल पर हमला किया गया. इस हमले में कई मासूमों की जान चली गई. अब्दुल्ला, जो पूर्व अफगान सरकार में राष्ट्रीय सुलह उच्च परिषद के प्रमुख रह चुके हैं, ने क्हमले की कड़ी निंदा की है. उन्होंने इस हमले को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है.

अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहम्मद नबी ने पाकिस्तान की ओर से काबुल पर हुए हमलों को लेकर चिंता व्यक्त की है. नबी ने बमबारी के शिकार हुए लोगों के बारे में लिखते हुए कहा, माएं अपने बेटों के नाम पुकारती थीं, उनका इंतजार करती रहीं. रमजान की 28वीं रात को उनकी जिंदगियां अधूरी रह गईं. राशिद खान ने भी हवाई हमले की कड़ी निंदा की है.

भारत ने काबुल में हमले की कड़ी निंदा की

भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक अस्पताल पर पाकिस्तान के हमले को कायरतापूर्ण और अमानवीय कृत्य बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि भारत सोमवार की रात काबुल के ओमिद नशा मुक्ति अस्पताल पर पाकिस्तान के बर्बर हवाई हमले की कड़ी निंदा करता है. यह हिंसा का एक कायरतापूर्ण और अमानवीय कृत्य है, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों की जान चली गई.

98वाँ अकेडमी अवॉर्ड्स

होर्मुज से 'नंदा देवी' जहाज भी भारत लौटा

47 हजार मीट्रिक टन एलपीजी लाया

नई दिल्ली, 17 मार्च. होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रूप से शिवालिक के बाद, एक और एलपीजी टैंकर नंदा देवी भारत आ चुका है. नंदा देवी होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करते हुए वडीनार बंदरगाह पर पहुंचा. यह जहाज अपने साथ 47 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लेकर आया है. मिडिल ईस्ट में गहराते संकट के बीच, होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाला यह दूसरा जहाज है. एक दिन पहले दूसरा एलपीजी टैंकर शिवालिक गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 46 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लेकर पहुंचा था. अधिकारियों का अनुमान था कि यह अकेला जहाज भारत की कुल एलपीजी आयात की जरूरत का लगभग एक दिन का हिस्सा पूरा कर सकता है.

24 घंटे के अंदर पीएनजी का नया कनेक्शन

- पाइप लाइन बिछाने तमाम मंजूरियों की जरूरत नहीं
- संयुक्त सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में दी जानकारी

नई दिल्ली, 17 मार्च (वार्ता) पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर सरकार ने पाइप के माध्यम से रसोई गैस का पीएनजी कनेक्शन लेने वालों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू करने के साथ- साथ नये आवेदनों को 24 घंटे में मंजूरी देने का निर्णय लिया है. पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध कराने के लिए सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ व्यापक अभियान चला रही है. इसके तहत पिछले कुछ दिनों में देश भर में लगभग 12,000 छापे मारे गए हैं और लगभग 15,000 सिलेंडर जब्त किए हैं. उत्तर प्रदेश में दस लोगों को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा घरेलू एलपीजी का उत्पादन भी 38 प्रतिशत बढ़ गया है.

संयुक्त सचिव ने कहा कि केन्द्र सरकार वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी में स्थानांतरित करने की कोशिश कर रही है. केन्द्र ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि पीएनजी की नई पाइपलाइन बिछाने के लिए सभी अनुमतियां स्वीकृत मानी जाएं और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए जाने वाले सड़क पुर्नस्थापना और अनुमति शुल्क को माफ किया जाना चाहिए. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों से दूर रहें, घबराएं नहीं, ऑनलाइन बुकिंग करें और एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी उनके घर पर की जाएगी.

कल होगी सुप्रीम कोर्ट में विजयपुर विधायक की सुनवाई

ग्वालियर, 17 मार्च. विजयपुर विधानसभा सीट के विधायक की अयोग्यता मामले की गूंज अब सुप्रीम कोर्ट में सुनाई देगी. कोर्ट 19 मार्च को विधायक मुकेश मल्होत्रा की याचिका पर सुनवाई करेगा. मुकेश मल्होत्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई करेंगे. बता दें कि 9 मार्च को हाईकोर्ट ने विजयपुर विधायक मामले में सुनवाई करते हुए मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन शून्य करने के बाद 15 दिन का समय सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए दिया था. 24 मार्च को यह 15 दिनों की समय सीमा पूरी हो रही है. ऐसे में 19 मार्च को होने वाली सुनवाई अहम होगी.

केंद्र से एमपी को मिलेंगे 19 हजार करोड़

- मंजूरी के पहले दिन ही मप्र ने किया केंद्र से एमओयू
- मामला जल जीवन मिशन 2.0 का

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 17 मार्च. केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन की अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ाने और इसे जल जीवन मिशन 2.0 के रूप में पुनर्गठित कर लागू करने को मंजूरी दी है. मिशन के लिए कुल व्यय बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ किया है, जिसमें केंद्र सरकार की सहायता 3.59 लाख करोड़ होगी. इस मिशन के तहत मप्र को लगभग 19 हजार करोड़ की केंद्रीय सहायता मिलेगी.

जल जीवन मिशन 2.0 योजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के पहले ही दिन मप्र सरकार ने केंद्रीय जल शक्ति और पेयजल मंत्रालय से इस संबंध में एमओयू किया, जिसके तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय पेयजल योजना के लिए पाइपलाइन बिछाने से लेकर पूरी अधोसंरचना का निर्माण करना जिससे पेयजल हर ग्रामीण तक पहुंच सके.

इसका मुख्य उद्देश्य पंचायत की साझेदारी से जलापूर्ति और जल संचयन छोटे-छोटे गांव तक पहुँचाना है. जल शक्ति मंत्रालय में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी,आर पाटील, जल शक्ति राज्यमंत्री वी. सोमन्ना और मप्र की ओर से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके, प्रमुख सचिव पी. नरहरि सहित केंद्र और राज्य के आला अधिकारी एमओयू के दौरान मौजूद रहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं.

ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधारने महत्वपूर्ण पहल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्वास जताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार दिसंबर 2028 तक जल जीवन मिशन के सभी कार्य पूर्ण कर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराएगी. उन्होंने कहा कि यह मिशन ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधारने और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है.

गुजरात बनेगा यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य

जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट

नई दिल्ली, 17 मार्च. गुजरात में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लागू होने की तैयारी तेज हो गई है. उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को यूसीसी का ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दिया.

यह रिपोर्ट तीन खंडों में तैयार की गई है. इसमें राज्य के सभी धर्मों व समुदायों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों पर एकसमान कानूनी ढांचे की सिफारिशें शामिल हैं. समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की. समिति ने विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा, जनता से राय-मशविरा, गहन चर्चाएं और सार्वजनिक परामर्श शामिल थे. रिपोर्ट में महिलाओं के समान अधिकारों और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है. साथ ही गुजरात की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने पर जोर दिया गया है. समिति के अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस सीएल मीणा, वरिष्ठ अधिवक्ता आरसी कोडेकर, पूर्व कुलपति डॉ. दक्षेश ठाकर और समाजसेवी गीता श्रॉफ शामिल हैं.

ईओडब्ल्यू ने 20 हजार की घूस लेते एमपीईबी के कम्प्यूटर ऑपरेटर को पकड़ा, जूनियर इंजीनियर फरार

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 17 मार्च। ईओडब्ल्यू ने जेई एमपीईबी के लिये 20 हजार की घूस लेते कम्प्यूटर ऑपरेटर को रंगे हाथ पकड़ा है। जेई किसान से खेत में डी. पी. कनेक्शन लगवाने के लिये 30 हजार रूपये की रिश्वत मांग रहा था। मुख्य आरोपी जेई कार्यवाही की भनक लगते मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है।

जानकारी के अनुसार प्रताप सिंह रावत पुत्र कुम्मेर सिंह रावत निवासी ग्राम दौनी ब्लॉक तहसील नरवर जिला शिवपुरी द्वारा ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू को एक शिकायत की गयी थी कि उसके पिता कुम्मेर सिंह रावत के नाम से ग्राम दौनी में कृषि भूमि पर ठेकेदार के माध्यम से दो डी. पी. लगवायी थी जिस पर विद्युत कनेक्शन के एवज में सुरजीत मिश्रा जूनियर इंजीनियर म.प्र.वि.वि.कं. करैरा जिला शिवपुरी द्वारा 30 हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई। शिकायत की पुष्टि के लिये वॉइस रिकॉर्डर के जरिए की गई। जिसके बाद ईओडब्ल्यू पुलिस ने आरोपी जेई सुरजीत मिश्रा के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया।

जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ई.ओ.डब्ल्यू. के निर्देश पर निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह कुशवाह के नेतृत्व में एक ट्रेप दल का गठन किया गया जिसके द्वारा मंगलवार को ट्रेप दल जब करैरा कार्यालय पहुंचा, तब सुरजीत मिश्रा ने फोन पर रिश्वत की राशि अपने कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रवीण कुशवाह को देने के लिये कहा। आवेदक द्वारा 20 हजार रूपये की राशि प्रवीण कुशवाह को देते ही टीम ने उसे दबोच लिया। ट्रेप दल ने रिश्वत की राशि जब्त करली है और कॅप्यूटर ऑपरेटर प्रवीण कुशवाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी सुरजीत मिश्रा जेई कार्यवाही की भनक लगते ही मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। कार्रवाई में निरीक्षक मदन मोहन मालवीय, एडीपीओ, अनिल कुमार लोधी, उप निरीक्षक शैलेन्द्र शर्मा, उप निरीक्षक हरिकिशोर चतुर्वेदी, प्र. आर. चन्द्रकला की भूमिका रही।

बंगाल में ममता-सुवेंदु के बीच होगा महामुकाबला

- टीएमसी ने 291 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की
- ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ेंगी चुनाव

कोलकाता, 17 मार्च (वार्ता) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए 294 में से 291 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए. ममता ने 74 विधायकों (करीब एक तिहाई) के टिकट काट दिए हैं। 15 विधायकों की सीटें बदली गई हैं।

पार्टी ने दार्जिलिंग की दो और कालिम्पोंग की एक सीट सहयोगी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा को दी है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में चुनावी समझौते का संकेत है. पार्टी की ओर से जारी सूची में 52 महिलाएं, 95 अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के तथा 47 अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार शामिल हैं. ममता बनर्जी एक बार फिर भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी, जबकि शशि पांजा को मानिकतला से टिकट दिया गया है. अभिनेता से राजनेता बने सोहम चक्रवर्ती को चांदीपुर से उम्मीदवार बनाया है, जबकि ज्योतिप्रिया मलिक हाबरा से चुनाव लड़ेंगे. कनई मंडल को इस बार टिकट नहीं दिया गया है. कोलकाता पोर्ट सीट से फिरहाद हाकिम को मैदान में उतारा है, जबकि मदन मित्रा को कामरहाटी से दोबारा उम्मीदवार बनाया है. पार्टी ने कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया है, जिनमें खड़दह से पूर्व पत्रकार देवदीप पुरोहित शामिल हैं.

लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी के पुत्र सिरसांया बनर्जी को उत्तरपाड़ा से टिकट दिया गया है, जबकि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नंदीग्राम सीट से पवित्र कर को उम्मीदवार बनाया गया है. इसके अलावा कुनाल घोष को बेहाला से मैदान में उतारकर पार्टी ने उन्हें पहली बार विधानसभा चुनाव का मौका दिया है. उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने चुनावी अभियान को गति दे दी है, जबकि राज्य में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना जताई जा रही है.

सिंहस्थ 2028 की तैयारियां | उज्जैन में 663 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन, गीता भवन और आरओबी की रखी गई आधारशिला

सिंहस्थ में आने वाला हर श्रद्धालु हमारा अतिथि होगा : सीएम

नवभारत न्यूज

उज्जैन. सिंहस्थ 2028 की तैयारियों और धार्मिक-सांस्कृतिक विकास को नई गति देते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ में आने वाला हर श्रद्धालु प्रदेश का अतिथि होगा और उसकी सुविधा व सम्मान सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

उन्होंने कहा कि सिंहस्थ-2028 का वैभव इस बार भूतो न भविष्यति होगा, अर्थात ऐसा आयोजन पहले कभी नहीं हुआ और भविष्य में भी दुर्लभ रहेगा.

कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उज्जैन में लगभग 663 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया. इनमें गीता भवन और विक्रम नगर रेलवे ओवर ब्रिज सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ-2028 केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का विश्व-समागम है, जहां देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु उज्जैन आएंगे. ऐसे में सरकार का प्रयास है कि उज्जैन को आधुनिक सुविधाओं से युक्त, स्वच्छ और व्यवस्थित आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाए, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. सिंहस्थ को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए राज्य सरकार ने 13 हजार 851 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को स्वीकृति दी है. वर्ष 2026-27 के बजट में सिंहस्थ की तैयारियों के लिए 3 हजार 60 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान रखा गया है. कार्यक्रम में 77 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से बनने वाले भव्य गीता भवन की आधारशिला रखी गई. इसके साथ ही 30 करोड़ 68 लाख रुपये की लागत से विक्रम नगर रेलवे ओवर ब्रिज का भूमिपूजन भी किया गया.

शहर और आसपास के क्षेत्रों में 11 नई सड़कों के निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया है, जिससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और सिंहस्थ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन केवल धार्मिक नगरी ही नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का भी केंद्र रहा है. यही वह भूमि है जहां भगवान श्रीकृष्ण ने सांदीपनि आश्रम में 64 कलाओं और 14 विद्याओं का अध्ययन किया और जहां से श्रीकृष्ण-सुदामा की पवित्र मित्रता की शुरुआत हुई. इसी भूमि पर धर्म, ज्ञान और संस्कृति की परंपरा आज भी जीवंत है.

प्रधानमंत्री का मिल रहा सहयोग : डॉ. यादव

सीएम बोले केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने एन एच 752 डी के बदनावर-पेटलावद-थांदला खंड को फोर लेन बनाने की स्वीकृति दी है, जिससे उज्जैन का संपर्क दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से और मजबूत होगा तथा क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी.